# धनेश को बचाइए

राष्ट्रीय सहारा, 29-9-13

भारतीय विज्ञान संस्थान और मैसूर के नेचर कंजरवेशन फाउंडेशन ने अपने एक अध्ययन में देश में घटते वनक्षेत्र के लिए धनेश नाम के पक्षी के शिकार को भी एक बड़ा कारण माना है। यह अध्ययन अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा बाघ संरक्षित क्षेत्र और मियाओ अभयारण्य में किया गया। ये दोनों संरक्षित वन क्षेत्र धनेश नाम के दुर्लभ पक्षी का भी आवास हैं। अपनी विशिष्ट चोंच के कारण धनेश किसी फल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समर्थ होता है और फल खाने के बाद दूर-दराज छोड़ दिया गया उसका बीज वन क्षेत्र को आबाद करता रहता है। प्रकृति प्रदत्त इस विशिष्टता के कारण धनेश को जंगल के किसान की उपमा दी जाती है लेकिन दुर्भाग्य से जंगल का यह किसान मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़कर खुद तो लुप्त होने की कगार पर है ही, खास किस्म के जंगली फल और फूलों के पेड़ों के विस्तार को रोकने का भी कारण बन रहा है। लंबी और नीचे की ओर घुमावदार चोंच के साथ ही चोंच के ऊपरी सिरे का लंबा उभार सींग की तरह लगने के कारण इसे अंग्रेजी में हार्नबिल नाम मिला है। दुनिया में इस बेशकीमती पक्षी की करीब 55 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 24 अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी दस प्रजातियां हैं। भारत और निकटवर्ती देशों में नौ प्रजातियां वन क्षेत्र आबाद करती हैं। धनेश की मजबूत चोंच के ऊपरी हिस्से में उसके सुरक्षा आवरण के रूप में जो हड्डीनुमा संरचना होती है, उससे चीन और जापान जैसे देशों में नक्काशीदार वस्तुएं बनायी जाती है। अपनी विलक्षण चोंच के कारण ही प्रकृति का यह बेशकीमती तोहफा मनुष्य के लालच का शिकार हो रहा है लेकिन इंसान को नहीं मालूम कि अपने तुच्छ सुख के लिए वह इस पर्यावरण मित्र का शिकार कर भविष्य में अपने ही अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा रहा है। भौतिक और अल्पकालिक विकास के नाम पर मनुष्य प्रकृति का भक्षक बन बैठा है अन्यथा प्रकृति का हर प्राणी पर्यावरण का रक्षक है। जैव विविधता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सृष्टि में मौजूद हर जीव-जंतु और पेड़ पौधे का समान महत्व है। जीवों में नन्हीं चींटी से लेकर विशालकाय हाथी और वनस्पति जगत में हरी काई व दूब से लेकर बूढ़े बरगद तक की धरती के पर्यावरण को सहेजने में अपनी-अपनी भूमिका है। लेकिन जिस मनुष्य को प्रकृति संरक्षण की दिशा में सबसे जरूरी भूमिका निभानी चाहिए थी, दुर्भाग्य से भौतिक विकास की अंधी दौड़ में वही उसका दुश्मन बन बैठा है। मानवजनित क्रिया कलापों से पैदा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ने प्रकृति को संकट में डाल दिया है। जल-जंगल-जमीन के बेतरतीब दोहन से प्रकृति का हर उपादान कराह रहा है। धनेश ही क्या, जीव व वनस्पति जगत की तमात प्रजातियां मनुष्य के लोभ की भेंट चढ़ या तो नष्ट हो गई हैं या नष्ट होने के कगार पर हैं। इसलिए प्रकृति संदर्भित किसी अध्ययन के प्रकाश में आते ही सचेत हो जाना चाहिए।

# परीक्षा और पैमाना

करीब साल भर पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पद्धति के मसले पर हिंदी की पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों के साथ अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया था और हजारों विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने की बात कही थी और किसी भी भाषा के साथ भेदभाव न होने देने का भरोसा दिलाया था। लेकिन तब विरोध के सबसे बड़े मुद्दे सीसैट यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र-द्वितीय में बाईस अंकों वाले अंग्रेजी अंश को हटाने और पास करने के लिए न्यूनतम अंक तैंतीस फीसद निर्धारित करने के अलावा इस पूरे मामले पर कोई ठोस नीति सामने नहीं आ सकी थी। अब सरकार ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं पर विचार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो आयु में छूट, योग्यता, पाठ्यक्रम और पद्धति जैसे अनेक मुद्दों की समीक्षा करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगर सरकार को लगेगा कि इस परीक्षा की पद्धति में बदलाव अनिवार्य हैं, तो उस पर विचार होगा। इस कवायद का लक्ष्य यह बताया गया है कि गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, कला आदि विभिन्न विषयों के उम्मीदवारों के बीच भेदभाव की जिस तरह की शिकायतें आती रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आइएएस और आइपीएस के चयन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर ऐसे आरोप तीखे रहे हैं कि यह गणित और इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से पढ़ाई करके इन परीक्षाओं में हाथ आजमाने वालों को फायदा पहुंचाता है। खासतौर पर, प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट के द्वितीय प्रश्नपत्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता को कमजोर तबकों को प्रतियोगिता से बाहर रखने के तौर पर देखा गया था। इस लिहाज से देखें तो देश के सर्वोच्च प्रशासनिक तंत्र में शामिल होने वालों के लिए परीक्षा-पूर्व के आग्रहों और आरोपों से निपटने के लिए एक स्पष्ट नीति की जरूरत बनी हुई थी।

दरअसल, मौजूदा परीक्षा पद्धति लागू होने के बाद से अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो अन्य भाषाओं के अभ्यर्थियों की सफलता की दर काफी तेजी से गिरी है। खासतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी इसे अपने लिए अवसरों के सिमटने के तौर पर देख रहे हैं। प्रश्नपत्रों के प्रारूप और उनकी भाषा ने कई सवाल खड़े किए हैं। सही है कि आज के दौर में अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित आदि की जानकारी जरूरी है। लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति का जो विस्तृत दायरा है, उसके मद्देनजर प्रशासनिक तंत्र में शामिल होने वालों के लिए दूसरे विषयों के बारे में जानना जरूरी क्यों न हो! फिर देश भर में शिक्षा-व्यवस्था की जैसी स्थिति है, उसमें साल-दो साल देर से पढ़ाई शुरू करने से लेकर शैक्षणिक सत्र में देरी जैसी कई वजहों से कमजोर तबकों के उम्मीदवारों को आयु में कुछ छूट की जरूरत हो सकती है। असल सवाल इन्हीं पहलुओं के बीच संतुलन बिठाने का है। अब इस मसले पर विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस परीक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार कर एक व्यापक नीति या दिशा-निर्देश का निर्धारण हो सकेगा।

# WAY OF THE VALLEY

## PM Modi made a strong pitch to Silicon Valley. He would also have noticed why innovation thrives there

The Indian Express, 29-9-15

PRIME MINISTER NARENDRA MODI'S visit to Silicon Valley, technology capital of the world, home to the likes of Apple and Google, has been widely deemed a resounding success. CEOs of some of the most innovative companies anywhere rolled out the red carpet in welcome, promising new investment in Digital India, the government's ambitious plan to connect each citizen to the internet and harness its potential to improve public services. Google confirmed plans to launch free WiFi in 500 railway stations across India; Microsoft pledged its help in bringing low-cost broadband to villages; and Qualcomm promised to invest $150 million in Indian startups. Modi engaged the tech community, many of whom are Indian or of Indian origin, with humour and anecdote. Of course, his reputation as an enthusiastically tech-savvy, social media-enabled PM had preceded him.

At the townhall-style discussion at Facebook HQ, India's PM spoke disarmingly of how social media was "like a guide" and an "easy textbook" for him, filling in for a "lack of education" and broadening his perspective. He acknowledged, too, its potential to radically transform the compact between governments and citizens — with Twitter and Facebook, with all their limits, acting as instant barometers of the public mood. He spoke of the ways in which social media can inject informality in starchy, protocol-obsessed diplomatic relations, describing how a "happy birthday" message for the Chinese prime minister went viral recently.

But the heartwarming tableau at Silicon Valley seemed at odds with the increasing parochialism and narrow-mindedness on display back home, be it the meat-ban contagion or ministerial talk of "cleansing" cultural areas that have been "Westernised". Clearly, Modi admires the entrepreneurial spirit and vivacity of Silicon Valley — as he put it, California is "one of the last places in the world to see the sun set. But it is here that new ideas see the first light of day". But if Silicon Valley exemplifies the virtues of creative disruption, it does so because it tolerates — no, celebrates — diversity and difference. The new ideas Modi praised so effusively are made possible in an environment that nurtures defiance and dissent and individuality. Insubordination is encouraged, not muzzled, and the blunt instrument of an internet block is not used as the knee-jerk retort to every perceived security risk. Modi may not be responsible for this strain of illiberalism that seems emboldened in his regime, but he has failed to forcefully distance himself from it, or to subdue it. Also, given his flair for technology, the prime minister must know that the internet respects few territorial boundaries — what happens on, say, Facebook in India, does not stay in India.

# TWO IN ONE

## Merger of Sebi and FMC will hopefully lead the way to a unified regulator for the financial market

The Indian Express, 29-9-15

THE FORMAL MERGER of the Forward Markets Commission (FMC) with Sebi on Monday is significant. India's regulatory architecture has so far been fragmented, with multiple oversight agencies sprouting after each reform announcement. Such fragmentation has given rise to turf battles between sectoral regulators. Policymakers have for long recognised the case for convergence between the securities and commodity derivatives markets. As finance minister, P. Chidambaram had proposed this in the 2004-05 budget, only for the move to be scuttled. But the Rs 5,600 crore National Spot Exchange scam, coupled with the FSLRC's recommendation, provided the government the opportunity to finally go ahead with the merger.

Most countries, barring the US and Japan, have a unified securities and commodity market regulator. There are good reasons to justify this design in India. For long, the FMC was forced to function like a subordinate office of the ministry of consumer affairs, without statutory powers. It was handicapped in terms of the regulatory and manpower resources required to police this growing segment. A merged regulator would not only enhance the integrity of financial markets, but also boost liquidity and improve the price-discovery process. A unified regulator may also have a salutary impact on the spot commodities market, while strengthening it with the transparent systems in place in the securities market. It helps that Sebi has evolved as a credible regulator in the last two decades.

But the merger will also pose challenges for Sebi. Among these are the jurisdictional powers of the state government over agricultural marketing and the political sensitivities involved with farm commodities. Price volatility in these cannot be compared to that in stocks or bonds. The growth of the commodity derivatives market has also been hobbled because of the lack of institutional players to impart greater liquidity in trading. But now, with an empowered regulator for the commodities market, there is a strong case for allowing these organised funds. Next, the government should look at merging the insurance and pension regulators, which can then be the precursor to a unified regulator for the financial market as a whole.

# Countdown To Paris

The Times of India, 30-9-15

## *Modi and Obama talk climate change, factoring in development is the challenge*

With the Paris climate change conference scheduled for later this year, it's welcome that Prime Minister Narendra Modi and US President Barack Obama devoted considerable attention to the subject during their latest interaction. The 21st session of the Conference of the Parties will take place between November 30 and December 11, where world leaders will try to forge a deal aimed at mitigating the effects of climate change. In light of the failure of 2009 climate talks in Copenhagen, much is riding on the Paris conference to delineate a fair and equitable approach towards curbing carbon emissions.

China and the US – the world's top two greenhouse gas emitters – have already declared their post-2020 emission targets. This is significant given that it was the failure of Beijing and Washington to reach a common understanding that had undermined the Kyoto Protocol. However, the Chinese-American consensus also puts pressure on India to commit to emission cuts. Against this backdrop, Modi has done well to highlight differentiated responsibilities on climate action.

That huge swathes of India are yet to benefit from 24x7 electricity supply means that emissions caps at a stage when India's per capita emissions still remain far below the US, Europe or China are inequitable and unacceptable. This is not to say India shouldn't play any role. Modi has reiterated India's commitment to climate change mitigation measures that take into account India's development needs. In this regard, India could commit to reducing its energy intensity to appropriate levels or alternately commit to keep its per capita emissions at levels below that of developed countries at any point in time.

Plus, India already plans to add 175 GW of renewable energy by 2022. It could do even more if the US and other developed nations fulfil their responsibilities as historic and current polluters and finance and facilitate clean technology transfers. In fact, as solar and wind energy technologies become price competitive with polluting energy from fossil fuels, India can become a low-cost production and design hub for renewable energy. Foreign investments in this sector could neatly dovetail with the Make in India initiative, creating jobs on the ground. For the Paris conference to succeed, developing and developed countries must help each other out. India can be the bridge between the two camps and help evolve a broad climate deal.

# रिजर्व बैंक के रेट कट तोहफे से जगी उम्मीदें

दैनिक भास्कर, 30-9-16

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने फिर सबको चौंका दिया। जब आमराय यही थी कि ब्याज दरों में बड़ी कटौती नहीं होगी, तब राजन ने रेपो रेट (वह दर जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा मुहैया कराता है) में आधा फीसदी कटौती कर दी। इसका एक प्रभाव होम लोन और उपभोक्ता सामग्रियों की खरीदारी के उद्देश्य से लिए जाने वाला कर्ज के सस्ते होने में होगा। आशा है कि इससे आवास क्षेत्र में मंदी का माहौल सुधरेगा तथा उपभोक्ता बाजार में मांग बढ़ेगी। ऐसा होना छोटी बात नहीं होगी, इसलिए कि आर्थिक स्थितियां लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। राजन ने भी ध्यान दिलाया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत तो हैं, लेकिन ये बहुत ठोस नहीं हैं। वैश्विक परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। इसी कारण रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की संभावना 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.4 फीसदी कर दी। इस हाल में अर्थव्यवस्था में गति फूंकने के लिए रिजर्व बैंक के पास एकमात्र उपाय ब्याज दर में कटौती था। उसने अपेक्षा से आगे बढ़ते हुए ऐसा किया। तीन कारणों से फिलहाल वह ऐसा करने की स्थिति में था। कच्चे तेल की कीमत निम्न स्तर पर बनी हुई है। इससे मुद्रास्फीति दर काबू में है। रिजर्व बैंक ने जनवरी 2016 में इस दर को छह फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य रखा था। मौजूदा हाल में अंदाजा है कि यह 5.8 प्रतिशत पर रहेगी। इसके अलावा सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बरता है। इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था की सेहत पर हो रहा है। इन परिस्थितियों में ब्याज दर गिरने से कोई अतिरिक्त चुनौती सामने नहीं आएगी, जबकि उपभोक्ता बाजार में तेजी आई तो उससे जीडीपी वृद्धि दर को गति देने में सहायता मिलेगी। वैसे एक पहलू जरूर है, जो इस आकलन के सच होने की राह में कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। अमेरिका के संघीय बैंक ने अपने यहां ब्याज दर घटाई तो उससे भारतीय वित्त बाजार से विदेशी निवेश का पलायन तेज हो सकता है। उसका दबाव भारतीय मुद्रा यानी रुपए पर पड़ेगा, जिसके परिमाणस्वरूप महंगाई लौट सकती है। संतोष की बात है कि रिजर्व बैंक इस आशंका के प्रति आगाह है। ऐसे में उसका ताजा फैसला सुविचारित लगता है। वैसे भी रघुराम राजन दबाव या भावावेश में निर्णय नहीं लेते। इसीलिए उनके नेतृत्व में रिजर्व बैंक ने सकारात्मक पहल की है, तो आशा करनी चाहिए कि वह अर्थव्यवस्था के बेहतर दिन लाने में सहायक बनेगी।

# Raghuram Obliges

## *RBI fast forwards rate cuts, Modi government must press on the accelerator now*

The Times of India, 30-9-15

In a vote of confidence on the Indian economy the RBI, headed by Raghuram Rajan, has cut repo rates by 50 basis points to 6.75%. This rate cut, the fourth and largest in the current year, will bring the policy rate down to the lowest level in four and a half years and hopefully give a leg up to both industry and consumers. While lower interest costs will persuade investors to take up more projects it will also induce a fall in EMIs on car, home and other loans, boosting consumption demand in the economy and thereby growth.

The unexpectedly large cut in rates seems to have been motivated by a number of factors. One is the growing downside risk to global growth and trade and plummeting international commodity prices – including that of oil – which has helped bring domestic consumer prices in line with RBI targets. Subdued demand in rural markets in tandem with weakening external demand has led to significant under-utilisation of capacity and persuaded investors to hold back new investments.

Another reason is that though RBI has cut policy rates 75 basis points in recent months, average lending rates of banks have fallen by only 30 basis points. RBI has now upped the pressure on banks to pass on the benefits of rate cuts to borrowers. Competition from new banks, expected to roll out operations in coming months, will also help. However, lower interest rates will boost growth only if the government pushes through reforms that reduce its flab and boost competition in the wider economy through measures such as the goods and services tax, the bankruptcy code or labour and land market reforms. Raghuram Rajan has done his bit by releasing the brakes on the economy. It's now up to the government to press on the accelerator.

# लड़कर लेनी है सुरक्षा परिषद की सीट

राजस्थान पत्रिका, 29-9-15

विश्लेषण

प्रमोद भार्गव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार व विस्तार की मांग अंगड़ाई लेती रही है। किंतु यह पहली बार संभव हुआ कि इस मांग को औपचारिक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्व-सम्मति से मंजूर किया। लगने लगा है कि सभी बड़े महाद्वीपों की आवाज इसमें शामिल कर ली जाएगी। भारत, जापान, जर्मनी व ब्राजील ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए मुहिम तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सदस्यता दिए जाने की प्रक्रिया की वार्ता को दस्तावेज आधारित बनाने के साथ, इसे समय-सीमा में पूरी करने की वकालत की है। क्योंकि 2005 में हुए वैश्विक सम्मेलन के बाद से इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के वर्षों में वैश्विक संघर्ष और संकट देखते हुए ऐसा किया जाना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। इस नाते सुरक्षा परिषद में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। तय है, यह परिघटना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। यदि परिषद में बदलाव की खिड़कियां खुलती हैं तो भारत सहित कुछ अन्य देशों को स्थायी सदस्यता मिल सकती है। अभी सर्वाधिकार परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के पास ही सुरक्षित हैं। यहां तक कि उन्हें महासभा द्वारा बहुमत से लिए निर्णय निरस्त करने का भी अधिकार है। यही एकाधिकार पी-5 देशों की शक्ति में विभाजन नहीं होने दे रहा है। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जन्म से लेकर अब तक असमानता बनी हुई है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसका अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फांस, रूस व चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। हालांकि इस उद्देश्य में परिषद को पूर्णतः सफलता नहीं मिली। भारत का दो बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक व अफगानिस्तान, अमेरिका व रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध एक न टूटने वाली कड़ी बन गया है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और

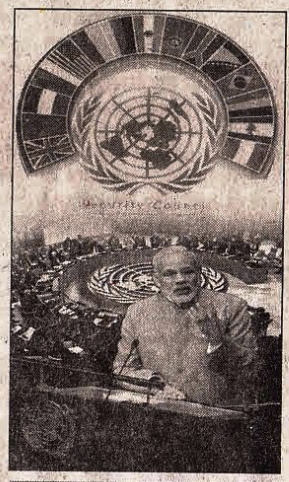

पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के आदेश को नहीं मानता। दुनिया के सभी शक्तिसंपन्न देश व्यापक मारक क्षमता के हथियारों के निर्माण और भंडारण में लगे हैं। बावजूद परिषद की भूमिका वैश्विक संगठन होने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास प्रतिबंध लागू करने व संघर्ष की स्थिति में सैनिक कार्रवाई की अनुमति देने के अधिकार देना शामिल हैं। इस नाते उसकी मूल कार्यपद्धति में शक्ति संतुलन बनाए रखने की भावना अंतर्निहित है।

1945 में परिषद के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक दुनिया बड़े परिवर्तनों की वाहक बन चुकी हैं। नई आर्थिक ताकतें, शक्ति के नए केंद्रों के रूप में विश्व मंच पर उभर रही हैं। एशियाई बौद्धिकता, पश्चिमी बौद्धिकता को जबरदस्त चुनौती दे रही है। इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को कहना भी पड़ा था कि अमेरिका के छात्र बंगलुरू और बीजिंग के तकनीकी पेशेवरों से मुकाबला करें ताकि मानव संसाधन के क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व बना रहे। चीन आज मनमानी में इसीलिए समर्थ है क्योंकि विश्व अर्थव्यस्था में उसकी नीतियां व उत्पादित वस्तुएं अनिवार्यता बन गई हैं। इसलिए परिषद में उसकी गलत बात पर भी शेष देश चुप्पी साध लेते हैं। असमानता की इस खाई को पुर्गठन के बाद ही पाटना संभव होगा।

- यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की खिड़कियां खुलती हैं तो भारत सहित कुछ देशों को इसमें स्थायी सदस्यता मिल सकती है। अभी सर्वाधिकार परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के पास सुरक्षित हैं। उन्हें महासभा द्वारा बहुमत से लिए निर्णय निरस्त करने का भी अधिकार है। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जन्म से लेकर अब तक असमानता बनी हुई है
- भारत न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है, बल्कि वीटो शक्ति पाने की पात्रता भी उसमे है। वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है

भारत लंबे समय से पुनर्गठन का प्रश्न उठाता रहा है। नतीजे में अन्य सदस्य देश भी इसके साझेदार बनते चले गए। परिषद के स्थायी व वीटोधारी देशों में अमेरिका, रूस व ब्रिटेन मौखिक समर्थन इस पक्ष में देते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है,जब संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से दो तिहाई से भी अधिक ने सुधार और विस्तार के लिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे का अहम मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब मसला परिषद में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का अनुत्तरित प्रश्न बन गया है, जिसका देर-सबेर हल निकलना तय है। हालांकि मोदी हल समय सीमा में चाहते हैं। दूसरा प्रस्ताव परिषद के पुनर्गठन से जुड़ा है। इसके तहत सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व को समतामूलक बनाना है। इस मकसद की पूर्ति के लिए परिषद के सदस्य देशों में से नए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी होगी। यह संख्या बढ़ती है तो असमानता दूर होने की संभावना स्वतः बढ़ जाएगी।

परिषद महासभा में इन प्रस्तावों का शामिल होना, बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि तो है, लेकिन परिणाम भारत व इसमें बदलाव की अपेक्षा रखने वाले देशों के पक्ष में आएंगे ही, इसमें संदेह है। अब एक साल तक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में परिषद की मौजूदा संरचना में सांगठनिक सुधार कैसे किए जाएं, इस पर विचार-विमर्श होता रहेगा। तब महासभा अध्यक्ष सैम कुटेसा पारित प्रस्ताव के क्रम में संपूर्ण सत्र की बैठक आहूत करेंगे। इसमें असमानता दूर करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। सभा में बहुमत से पारित होने वाली सहमतियों के आधार पर 'अंतिम अभिलेख' की रूपरेखा तैयार होगी। किंतु जरूरी नहीं कि अभिलेख किसी देश की इच्छाओं के अनुरूप ही हो। क्योंकि बहुमत से लाए गए प्रस्तावों को भी खारिज करने का अधिकार पी-5 देशों को है। यदि किसी नए देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल भी जाती है तो भी प्रश्न कायम रहेगा कि उन्हें वीटो की शक्ति दी जाती है या नहीं? इसलिए भारत के लिए फिलहाल प्रश्न अनुत्तरित ही है कि उसके लिए प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था में स्थायी सदस्यता पाने का रास्ता निष्कंटक हो गया है।

हालांकि भारत न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है, बल्कि वीटो शक्ति पाने की पात्रता भी उसमे है। वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। सवा अरब की आबादी वाले भारत में अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के वही संवैधानिक अधिकार हैं, जो बहुसंख्यक हिंदुओं के हैं। भारत ने साम्राज्यवादी मंशा के दृष्टिगत कभी किसी दूसरे देश की सीमा पर अतिक्रमण नहीं किया, जबकि चीन ने न सिर्फ तिब्बत में अतिक्रमण किया है, बल्कि उसकी नस्लीय पहचान मिटाने में भी लगा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन स्थायी सदस्यता हासिल करने में बाधा बने पेंच अपनी जगह बदस्तूर हैं।

भारत की जहां तक बात है तो परस्पर हितों के टकराव के चलते चीन नहीं चाहता कि भारत और जापान को सदस्यता मिले। ब्रिटेन व फ्रांस जर्मनी के प्रतिद्वंद्वी देश हैं। जर्मनी को सदस्यता मिलने में यही रोड़े अटकाने का काम करते हैं। महाद्वीपीय प्रतिद्वंद्विता भी अपनी जगह है। एशिया में भारत का प्रतिद्वंद्वी जापान है। लैटिन अमेरिका से ब्राजील, मैक्सिको व अर्जेंटीना सदस्यता के लिए प्रयासरत हैं तो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका व नाइजीरिया जोर-आजमाइश में लगे हैं। जाहिर है, परिषद का पुनर्गठन होता भी है तो भारत जैसे देशों को बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में प्रबल दावेदारी के साथ बेहतर कूटनीति का परिचय देना होगा। क्योंकि सुरक्षा परिषद में पुनर्गठन के प्रस्ताव ने, पी-5 देशों के शक्ति विभाजन का द्वार खोल दिया है। इस विभाजन में ही दुनिया के अधिक लोकतांत्रिक होने की उम्मीद अंगड़ाई ले रही है।